



करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश

जनवरी

(संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश

➤ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय	3
➤ खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 के मेसकॉट और टॉर्च का होगा अनावरण	4
➤ जल-संसाधन विभाग को सिंचाई में हासिल हुई विशेष उपलब्धियाँ	4
➤ बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार	5
➤ 17वीं ब्लाईंड चैलेंज कार रैली, 2022	6
➤ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच होगा एमओयू	6
➤ प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया	6
➤ एम.पी. टूरिज्म बोर्ड ने पीबीडी 2023 में 8 एमओयू साइन किये	7
➤ राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित	8
➤ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया	8
➤ प्रधानमंत्री ने किया इंदौर में सातवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का वर्चुअल शुभारंभ	9
➤ 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ब्रोशर लॉन्च	10
➤ कोषालयों में आधार आधारित भुगतान करने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य	10
➤ आरईसी से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 1000 करोड़ की सहायता देने का हुआ करार	11
➤ भारत अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल-2022	11
➤ केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिये चार महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी	12
➤ इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण	12
➤ राज्यपाल ने पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन के नवीन भवन और नई वीथिकाओं का भूमि- पूजन किया	13
➤ मध्य प्रदेश ट्रांसको ने ऊर्जाकृत किये बैरागढ़ सब स्टेशन में दो नए 220 के.व्ही. के सर्किट	13
➤ सिंगरौली को मिलेगा मेडिकल कॉलेज भवन की सौगात	14
➤ गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल	14
➤ मुख्यमंत्री द्वारा पुस्तक 'वेलोपेथी-माय नेचुरल हीलर'का विमोचन	15
➤ चित्रकूट में गुप्त गोदावरी में नजर आई तीसरी गुफा	15
➤ सौर ऊर्जा से रोशन होगी साँची	16
➤ 13वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस	16
➤ नाबार्ड 2023-24 में मध्य प्रदेश को 2 लाख 58 हजार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा	17
➤ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय	17
➤ ओरछा में 550 किमी. की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन	18
➤ राज्यपाल ने गणतंत्र का उत्सव 'लोकरंग' का किया शुभारंभ	18
➤ प्रदेश की चार विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित	19
➤ मध्य प्रदेशीय और भारतीय देशी गायों के लिये नवीन पुरस्कार योजना	20
➤ 'यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज' प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की दो युवतियाँ चयनित	20
➤ लाडली बहना योजना	21
➤ मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मेघा इंजीनियरिंग के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित	21

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

3 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में 45 सी.एम. राइज विद्यालयों के लिये 1807 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किये जाने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 45 स्कूलों के निर्माण के लिये डीपीआर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए। विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर 45 सर्वसुविधायुक्त स्कूलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश में कुल 9 हजार 200 सी.एम. राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। इसकी मंत्रि-परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति जुलाई, 2021 में जारी की जा चुकी है। इसमें से प्रथम चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग में तथा शेष 95 स्कूल जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में मंत्रि-परिषद द्वारा 2 हजार 660 करोड़ रुपए की लागत के 73 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
- मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में 433 नई पी.जी. सीट वृद्धि का निर्णय लिया। तीनों चिकित्सा महाविद्यालय के लिये कुल 438 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
- चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये पी.जी सीट्स की वृद्धि होने से प्रदेश को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
- मंत्रि-परिषद ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थाओं से संभाग स्तर पर दिये जाने के लिये योजना का अनुमोदन एवं ऑफलाइन कोचिंग को प्रतिवर्ष और ऑनलाइन कोचिंग पायलेट प्रोजेक्ट में आगामी 4 वर्षों के संचालन के लिये वित्तीय भार 30 करोड़ 54 लाख 71 हजार रुपए का अनुमोदन किया।
- इस योजना में ऑफलाइन कोचिंग के लिये वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक (2 वर्षीय पाठ्यक्रम अनुसार) 1600 विद्यार्थियों को ऑफलाइन कोचिंग से लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन कोचिंग के लिये 10 विशिष्ट विद्यालयों के 25 विद्यार्थियों के मान से 4 वर्षों में कुल 250 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में आम सहमति और निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने की योजना को पुनरीक्षित करते हुए अब नई श्रेणियाँ एवं पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपए। सरपंच पद के लिये वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रुपए; ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, उन्हें 7 लाख रुपए; ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं 12 लाख रुपए; पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर 15 लाख रुपए दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- मुख्यमंत्री द्वारा 7 दिसंबर 2022 को सरपंचों के राज्य-स्तरीय उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि सरपंचों का मानदेय 1,750 से बढ़ाकर 4,250 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। इस संदर्भ में पंचायत राज संचालनालय से जारी आदेश का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया। इससे प्रदेश की 23 हजार 12 ग्राम पंचायतों के सरपंच, दूरभाष एवं सत्कार भत्ता सहित 4,250 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त करेंगे।

- मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की 'ग्रेन बैंक' योजना के प्रावधान के अनुसार 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से गरीब असहाय जनजातीय परिवारों को वितरित 15 करोड़ 75 लाख रुपए का खाद्यान्न वापस न मिलने पर इसकी लागत पर शासन को हुई हानि राशि 15 करोड़ 75 लाख रुपए का अपलेखन किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनागत पूर्व में प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती एवं धात्री माता को 5 हजार रुपए दिये जाने का प्रावधान था। मंत्रि-परिषद ने योजना के नवीन दिशा-निर्देशों में प्रथम प्रसव पर 5 हजार रुपए के साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका के जन्म होने पर योजना के पात्र हितग्राही को 6 हजार रुपए दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की। 'मिशन शक्ति' के 'सामर्थ्य' घटक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 प्रदेश के सभी जिलों में परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की स्वीकृति भी दी गई।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 के मेसकॉट और टॉर्च का होगा अनावरण

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में 7 जनवरी को भोपाल के शौर्य स्मारक में रंगारंग कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 के मेसकॉट, टॉर्च और एंथम का अनावरण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 के पाँचवें संस्करण की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस भव्य खेल आयोजन में 13 दिन तक 8 अलग-अलग शहरों के 23 गेम वेन्यू में 6 हजार खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पाँचवाँ संस्करण प्रदेश के 8 शहरों- भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन (महेश्वर) में होगा। एक गेम (साइकिलिंग) दिल्ली में आयोजित होगा।
- पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात् कयाकिंग-कैनोइंग, कैनो सलालम और तलवारबाजी आदि प्रतिस्पर्धाएँ खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा होंगी।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 में 303 अंतर्राष्ट्रीय और 1089 राष्ट्रीय ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया के लिये लगभग 2 हजार कॉलिंटियर अलग-अलग गेम वेन्यू में तैनात रहेंगे।

जल-संसाधन विभाग को सिंचाई में हासिल हुई विशेष उपलब्धियाँ

चर्चा में क्यों ?

6 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश जल-संसाधन विभाग ने बीते वर्षों में सिंचाई के क्षेत्र में हासिल की गई अनेक उपलब्धियों का ब्यौरा जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि सिंचाई क्षमता में बीते दो साल में 3 लाख 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई है।
- विभाग द्वारा वर्तमान में 37 लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। तवा परियोजना के कमांड में जायद फसल के लिये किसानों को 89 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल रही है।
- वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 840.3 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की गई है। वहीं 2022-23 में सितंबर तक 266.11 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली की जा चुकी है।
- विभाग ने वर्ष 2020-21 में एक लाख 15 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित करने के लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 16 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की। वहीं 2021-22 के लक्ष्य एक लाख 70 हजार हेक्टेयर के विरुद्ध एक लाख 71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता विकसित की गई। कुल सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करने के लक्ष्य को 31 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

- विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में बीते दो वर्ष में कुल 126 नयी वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की गईं। इनमें चार वृहद्, 10 मध्यम और 112 लघु परियोजनाएँ शामिल हैं। इन सभी 126 सिंचाई परियोजनाओं की लागत 6 हजार 700 करोड़ रुपए है। इन नयी सिंचाई परियोजनाओं से 3 लाख 34 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
- मध्य प्रदेश में बहु प्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। 44 हजार 605 करोड़ रुपए लागत की इस राष्ट्रीय परियोजना से प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही लगभग 41 लाख आबादी को पेयजल की सुगम आपूर्ति होगी।
- इस परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका पूर्ण उपयोग मध्य प्रदेश करेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना से राज्य के 10 जिलों की 28 तहसील के 2040 ग्राम लाभांविता होंगे।
- मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भू-जल स्तर को बढ़ाने, पेयजल संकट को दूर करने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अटल भू-जल योजना' प्रारंभ की गई है। लगभग 314 करोड़ 54 लाख रुपए लागत की इस परियोजना में प्रदेश के 6 जिलों के 9 विकासखंड के 678 गाँवों में जन-भागीदारी से जल-संवर्धन एवं भू-जल स्तर में सुधार के कार्य किये जा रहे हैं।
- मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल अंचल में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिये 6,601 करोड़ की 'श्रीमंत माधवराव सिंधिया नवीन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना' प्रारंभ की जा रही है। इस परियोजना से प्रदेश के गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिले में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 6 जलाशय का निर्माण होगा। साथ ही सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, पर्यटन एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। क्षेत्र का भू-जल स्तर भी बढ़ेगा।
- गौरतलब है कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर आधारित योजनाओं का निर्माण करने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। विभाग की वर्तमान में निर्माणाधीन 55 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में आधुनिक दबाव युक्त पाइप आधारित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।
- जल-संसाधन विभाग ने बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में 'डेम सेफ्टी रिव्यू पैनेल' गठित है। पिछले 5 वर्ष में 148 करोड़ रुपए की लागत से 25 बांध की मरम्मत का कार्य किया जा चुका है। आने वाले 5 वर्ष में 27 बांध की सुरक्षा एवं मरम्मत की जाएगी। इसके लिये विश्व बैंक के सहयोग से 551 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है।

बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

6 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिये इनाम योजना घोषित की है।

प्रमुख बिंदु

- अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।
- बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी।
- कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
- कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।

17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली, 2022

चर्चा में क्यों ?

8 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्वयंसेवी संस्था आरुषि द्वारा भोपाल में आयोजित 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली, 2022 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- स्वयंसेवी संस्था आरुषि द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और होटल ताज लेक फ्रंट के साथ मिलकर एलआईसी, मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड एक्वेरियस के सहयोग से इस कार रैली का आयोजन किया गया।
- इस वर्ष रैली को गुलजार साहब ने नाम दिया- 'हमसफर' यह संदेश देते हुए कि हमें सभी पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को विकलांगों के अनुकूल बनाना है और हर तरह से विकलांगों को अपने साथ शामिल करना है।
- प्रतियोगिता को दो वर्गों में बाँटा गया- विशेषज्ञ वर्ग जो पूर्व में आरुषि की कार रैली में से किसी में भी विजेता रहा हो। 2. नौसिखिये वर्ग जिन्होंने कोई भी रैली नहीं जीती है या पहली बार भाग ले रहे हैं।
- न्यूनतम पेनल्टी अंकों के साथ समाप्त होने वाले प्रतियोगियों को विजेता घोषित किया गया। प्रत्येक मिनट की देरी के लिये एक पेनल्टी अंक और चेक पाइंट्स पर एक मिनट पहले प्रवेश करने पर 5 पेनल्टी अंक थे।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच होगा एमओयू

चर्चा में क्यों ?

9 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवाचार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) संगठन के चिकित्सकों के साथ विशेष चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया।
- चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि अमेरिका में डॉक्टर्स के प्रतिष्ठित संगठन के साथ एमओयू से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम विकसित हो सकेंगे।
- मंत्री सारंग ने अमेरिका से आए चिकित्सकों के संगठन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (AAPI) के साथ चिकित्सा शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में परस्पर आदान-प्रदान के लिये विस्तृत चर्चा की।
- मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत होने जा रहे इस एमओयू में AAPI द्वारा मध्य प्रदेश के चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों की केपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, चिकित्सा के विषय-विशेषज्ञता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में तकनीकी सहयोग, चिकित्सा शोध के क्षेत्र में कोलेबोरेशन के साथ ही चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के लिये ऑनलाइन लेक्चर्स एवं वर्कशॉप में अपना सहयोग प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

9 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 'आजादी का अमृत महोत्सव- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान' विषय पर पहली बार डिजिटल पीबीडी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने सुरक्षित, कानूनी, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये एक स्मारक डाक टिकट 'सुरक्षित जाएँ, प्रशिक्षित जाएँ' भी जारी किया।
- उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने और प्रवासी भारतीय को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- इंदौर में 08-10 जनवरी, 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वाँ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन का विषय 'प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिये विश्वसनीय भागीदार' है। लगभग 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय सदस्यों ने पीबीडी कन्वेंशन के लिये पंजीकरण कराया है।
- सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' की थीम पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो गौरवशाली युग को एक बार फिर से सामने लाती है।
- अमृत काल की अगले 25 वर्षों की यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा भारत की अनूठी वैश्विक दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में इसकी भूमिका को मजबूत किया जाएगा।
- पीबीडी कन्वेंशन में पाँच विषयगत पूर्ण सत्र होंगे-
 - ◆ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 'नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका' पर पहला सत्र।
 - ◆ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता और विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह की सह-अध्यक्षता में 'अमृत काल में भारतीय हेल्थकेयर इको-सिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका: विजन- 2047' पर दूसरा सत्र।
 - ◆ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में 'भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना - शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना' पर तीसरा सत्र।
 - ◆ शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की अध्यक्षता में 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना- भारतीय डायस्पोरा की भूमिका' पर चौथा सत्र।
 - ◆ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 'राष्ट्र निर्माण के लिये एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की क्षमता का उपयोग' पर पाँचवा सत्र।
- 17वें पीबीडी कन्वेंशन का महत्त्व है, क्योंकि यह चार साल के अंतराल के बाद और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार एक वास्तविक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महामारी के दौरान 2021 में पिछला पीबीडी सम्मेलन वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था।

एम.पी. टूरिज्म बोर्ड ने पीबीडी 2023 में 8 एमओयू साइन किये

चर्चा में क्यों ?

9 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इंदौर में ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर में एम पी टूरिज्म पवेलियन में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन (गोपियो) के 8 देश के चेप्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- यह एमओयू फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस, मॉरीशस, रीयूनियन द्वीप, मार्टीनिक, श्रीलंका, गोपियो इंटरनेशनल, मलेशिया एवं मॉरीशस के साथ किये गए।
- एमओयू पर प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने टूरिज्म बोर्ड की ओर से और जीओपीआईओ के 8 देशों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किये।

- प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यह एमओयू प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के विकास में अधिक सहयोग स्थापित करने, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से किया गया है। यह अनुसंधान, संवर्धन और पर्यटन विकास में सहयोग को मजबूत करने, बढ़ावा देने और विकसित करने का भी प्रयास है।
- प्रमुख सचिव ने कहा कि भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में देश का एक सांस्कृतिक राजदूत है। उन्होंने सभी प्रवासी भारतीयों से भारत की संस्कृति का विदेश में प्रचार करने की अपील भी की।
- अध्यक्ष जीओपीआईओ फ्रांस राजाराम मुनुस्वामी ने कहा कि एमओयू दोनों देश के लिये उपयोगी रिश्ते का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह मध्य प्रदेश पर्यटन और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के बीच मौजूद बंधन को और मजबूत करेगा।

राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित

चर्चा में क्यों ?

10 जनवरी, 2023 को राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 में कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करने एवं समीक्षा के लिये 'राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड' गठित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भूमि अर्जन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्य की समीक्षा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विषय-विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त करना और राज्य शासन को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना बोर्ड के दायित्व होंगे।
- इन दायित्वों के अधीन 'मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग' को 'राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड' भी घोषित किया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया

चर्चा में क्यों ?

10 जनवरी, 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में तीन दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन किया। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष रूप से शामिल हुए।
- राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मान प्रवासी भारतीयों को दिये जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। यह उनके भारत और अन्य देशों के लिये किये गए कार्यों और योगदान को प्रदर्शित करता है।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ प्रवासी भारतीयों ने नमो ग्लोबल पार्क में पौधे भी लगाए हैं। अतिथियों को क्यू आर कोड दिये गए हैं, जिसमें वे रोपे गए पौधे की देख-रेख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रवासी भारतीय हैं-
 - ◆ सामुदायिक कल्याण- डॉ. मोहम्मद इरफान अली (राष्ट्रपति, गुयाना), डॉ. कन्नन अम्बलम (इथोपिया), सुश्री रीना विनोद पुष्करना (इजराइल), परमानंद सुखमल दासवानी (कांगो), मोहनलाल हीरा (दक्षिण अफ्रीका), सिक्कुमार नादेसन (श्रीलंका), डॉ. देवचंद्रभोस शर्मा (सूरीनाम)।
 - ◆ सामुदायिक कल्याण तथा मेडिसिन- डॉ. अमल कुमार मुखोपाध्याय (जर्मनी), डॉ. एलेक्सजेंडर जॉन (ब्रुनेई)।
 - ◆ सामुदायिक कल्याण तथा व्यापार- अमित कैलाशचंद्र लाथ (पोलैंड), संजय कुमार शिव भाई पटेल (दक्षिण सूडान), डॉ. दर्शन सिंह धालीवाल (अमेरिका), सिद्धार्थ बालचंद्रन (संयुक्त अरब अमीरात)।
 - ◆ विज्ञान, तकनीक और शिक्षा- प्रोफेसर जगदीश चंद्रपति (आस्ट्रेलिया), डॉ. अर्चना शर्मा (स्विट्जरलैंड)।
 - ◆ शिक्षा- संजीव मेहता (भूटान), सुश्री मक्सूदा सफ़ी श्योटानी (जापान), डॉ. राजागोपाल (मेक्सिको)।
 - ◆ शिक्षा तथा सामुदायिक कल्याण- जस्टिस फ्रैंक ऑर्थर सीपरसाद (त्रिनिदाद और टोबेगो)।
 - ◆ कला-संस्कृति- दिलीप लुंडो (ब्राजील), डॉ. वैकुंठम अबयर लक्ष्मणम (कनाडा), डॉ. जुगुन्नदर सिंह निजर (क्रोएशिया)।

- ◆ सूचना प्रौद्योगिकी- प्रोफेसर रामजी प्रसाद (डेनमार्क)।
- ◆ व्यापार- पीयूष गुप्ता (सिंगापुर), अशोक तिवारी (उज्बेकिस्तान)।
- ◆ मीडिया- चंद्रकांत पटेल (यूनाइटेड किंगडम)।

प्रधानमंत्री ने किया इंदौर में सातवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का वर्चुअल शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में सातवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस समिट का समापन 12 जनवरी को होगा।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट रूप से शामिल हुए और संबोधन दिये।
- अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आगामी चार-पाँच वर्ष में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यह वैश्विक पटल पर भारत का दशक नहीं, बल्कि भारत की शताब्दी है।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में हो रही यह समिट सही अर्थ में वैश्विक है। इस समिट में जहाँ सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति आए हैं, वहीं समिट में मॉरीशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिंबाब्वे के खनिज मंत्री भी आए हैं। विश्व के 33 देश के प्रतिनिधि तथा कुल 84 देश के 431 डेलिगेट्स आए हैं।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये 9 सेशन में निवेशकों से चर्चा होगी। मध्य प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही अन्य सेशन में सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये वित्तीय सहायता, एक्सेस मध्य प्रदेश कंपलीट बिजनेस साल्यूशन विषय पर भी निवेशकों से चर्चा होगी। एक अन्य सेशन में इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूईई (12 यू 2) समूह साझा निवेश पर भी चर्चा होगी।
- समिट के दूसरे दिन सेशन में प्रमुख रूप से भारत की 5 ट्रिलियन की इकॉनामी में मध्य प्रदेश का योगदान, एयरो स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संभावनाएँ, भारत में मैनुफैक्चरिंग को गति देने में मध्य प्रदेश का योगदान और शिक्षा और कौशल विकास पर मध्य प्रदेश में बेहतर निवेश की संभावना विषय पर निवेशकों के बीच चर्चा होगी।
- विशेष सेशन में मध्य प्रदेश में स्टार्ट-अप के लिये अनुकूल वातावरण पर चर्चा होगी। इन सभी सेशन में विषय-विशेषज्ञ मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल खूबियों के बारे में जानकारी देंगे।
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका से समिट में वर्चुअली जुड़ते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में देश का एक चौथाई ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन होता है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश का योगदान 20% है। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में भी पहचान बना रहा है।
- जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पार्थ मित्तल ने कहा कि हमारे समूह की प्रदेश में 4500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इसके अंतर्गत पन्ना में सीमेंट प्लांट और पीथमपुर में 1500 करोड़ रुपए की लागत से पेंट की इकाई लगाई जा रही है।
- रिलायंस ग्रुप के निखिल आर. मेसवानी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक प्रदेश की सभी तहसीलों में 5जी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। किरायायती डिजिटल सुविधाओं से छात्रों, किसानों और आम आदमी को लाभ होगा। रिलायंस ग्रुप राज्य में अब तक 22 हजार 500 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है तथा 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।
- अडानी ग्रुप के प्रणव अडानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अडानी समूह 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। समूह द्वारा धार, गुना, दमोह, उज्जैन और इंदौर में फूड पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।

8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का ब्रोशर लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

13 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकास्ट में आठवें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के कर्टेन रेजर कार्यक्रम के तहत विज्ञान महोत्सव का ब्रोशर लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- आठवाँ विज्ञान महोत्सव भोपाल में 21 से 24 जनवरी तक मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया जाएगा। अब तक इस महोत्सव के सात आयोजन देश के विभिन्न शहरों में हो चुके हैं।
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लगभग दो लाख स्क्वायर फीट की जगह पर लगने वाली प्रदर्शनी में इसरो, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डीआरडीओ सहित विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले भारत के 300 से अधिक संस्थानों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगे।
- साथ ही 19 जनवरी, 2023 को रन फॉर साइंस का आयोजन होगा। विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह रन टी.टी. नगर स्टेडियम से शुरू होकर मैनिट परिसर पर समाप्त होगी।
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) के कार्यकारी निदेशक अरविंद रनाडे ने बताया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2015 में आईआईटी दिल्ली से हुई थी। इस महोत्सव के दौरान स्टूडेंट्स साइंस विलेज कार्यक्रम भी होगा। साइंस विलेज में मध्य प्रदेश के विभिन्न दूरस्थ इलाकों के 1500 बच्चे शामिल होंगे, जो विज्ञान और इसके चमत्कार को करीब से देख सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, स्टार्टअप हब जैसी गतिविधियाँ होंगी।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सीनियर साइंटिस्ट संजय मिश्रा ने बताया कि यह महोत्सव कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह एक ऐसा समारोह है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स से लेकर रिटायर्ड अधिकारी सहित देश के विशिष्ट वैज्ञानिक शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि यह विज्ञान के व्यापक प्रचार-प्रसार का आयोजन है। इस महोत्सव में 15 गतिविधियाँ जैसे- आर्टिजन टेक्नोलॉजी, विलेज वोकल फॉर लोकल, न्यू एज टेक्नोलॉजी शो, मेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज, स्टार्टअप कॉन्क्लेव होंगी। इनमें 10 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे।

कोषालयों में आधार आधारित भुगतान करने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य

चर्चा में क्यों ?

13 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कोषालयों में आधार आधारित भुगतान के माध्यम से हितग्राहियों को भुगतान सुविधा देने वाली नयी व्यवस्था का शुभारंभ किया, जिससे प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जो यह सुविधा प्रदान करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि कोषालयों में लागू एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिये विगत कुछ समय से नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। डिजिटल लेखा प्रेषण, बिल पारित करने में ई-साइन, आम नागरिक को कर/राजस्व का भुगतान करने के लिये ई-चालान में सभी भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इससे न सिर्फ वित्तीय व्यवहार में आसानी हुई बल्कि वित्तीय अनुशासन लाने में भी सफलता मिली है।
- अब वित्तीय कार्य-प्रणाली को और सरल, सुदृढ़ एवं हितग्राही मूलक बनाने के उद्देश्य से आधार आधारित भुगतान की नयी व्यवस्था 16 जनवरी, 2023 से प्रदेश के सभी कोषालयों में लागू हो जाएगी। नयी व्यवस्था से दोहरे लाभ को चिन्हित कर रोका जा सकेगा। साथ ही असफल भुगतान में भी कमी आएगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को वर्ष 2010 से उनके बैंक खाते में सीधे ई-भुगतान किया जा रहा है। समय की आवश्यकता और वित्तीय प्रबंध में आ रहे बदलावों को देखते हुए ई-भुगतान प्रणाली को प्रभावी बनाते हुए अब हितग्राहियों को बैंक खाते के साथ-साथ आधार आधारित भुगतान करना भी संभव हो गया है।

- वित्त मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में आधार आधारित भुगतान के साथ बैंक खाता आधारित ई भुगतान को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली से समस्त कोषालय में 16 जनवरी, 2023 से प्रारंभ किया जा रहा है।
- ई-कुबेर लागू होने से प्रदेश के समस्त ई-भुगतान तेजी से संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में प्राप्त होंगे। यह प्रणाली सभी कार्य दिवस पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
- वित्त मंत्री ने बताया कि नयी प्रणाली को लागू करने से आँकड़ों का मिलान आसान हो जाएगा। पूर्व में बैंकों द्वारा प्राप्त एवं भुगतान की जानकारी भौतिक रूप से कोषालय को दी जाती थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक और महालेखाकार को भेजी जाती थी, जिसमें आँकड़ों की भिन्नता की कई समस्याएँ थीं। ई-कुबेर के आने से भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे व्यवहार होंगे और वित्तीय लेन-देन के आँकड़ों के मिलान की समस्या समाप्त होगी।
- इस दिशा में आगे बढ़ते हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में प्रदेश के योगदान को और बढ़ाया जाएगा। वर्तमान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के स्थान पर आधुनिक तकनीकी नवाचारों को शामिल करते हुए फेसलेस, पेपरलेस, कांटेक्टलेस एवं कैशलेस वित्तीय व्यवहारों को लागू करने तथा यूजर फ्रेंडली सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से IFMIS Next Gen का विकास किया जा रहा है।

आरईसी से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 1000 करोड़ की सहायता देने का हुआ करार

चर्चा में क्यों ?

14 जनवरी, 2023 को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) द्वारा 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु करार हुआ।

प्रमुख बिंदु

- आरईसी ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिये एमपी डिस्कॉम को 5000 करोड़ रुपए की राशि देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इसके लिये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- इसके अलावा आरईसी ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ भी 15 हजार 86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
- आरयूएमएसएल से हुए करारनामे के अनुसार आरईसी द्वारा अक्षय ऊर्जा पार्कों तथा परियोजनाओं के विकास, बिजली वितरण सहित संबंधी बुनियादी ढाँचे को कवर करने वाली नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिये 1000 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है।
- रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिये नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डेवलपर नामांकित किया गया है।
- इस परियोजना को प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। प्रदेश का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 तक नवकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2027 तक 30 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत उत्पादन करने का है।
- इसके अतिरिक्त आरईसी ने विश्व बैंक की साझेदारी में चुनिंदा राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिये एक वित्त पोषण योजना भी तैयार की है। इससे आरईसी-विश्व बैंक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्तीय सहायता की कुल मात्रा एक अरब अमरीकी डालर उपलब्ध होगी।

भारत अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल-2022

चर्चा में क्यों ?

16 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकॉस्ट) के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि स्कूली बच्चों एवं जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में आठवें अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- आठवें साइंस फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान भारती (विभा) तथा मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मेनट) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
- इस साइंस फेस्टिवल के लिये मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकॉस्ट), भोपाल नोडल एजेंसी है।
- 21 से 24 जनवरी के दौरान इस विज्ञान महोत्सव में देश भर से 8 हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आजादी के अमृतकाल में हो रहे इस महोत्सव का मुख्य विषय 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर देश' है।
- मेपकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि इस साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत ही 19 जनवरी से रन फॉर साइंस मैराथन का संयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की ओर से किया जा रहा है। साढ़े तीन किलोमीटर की मैराथन भोपाल के टी.टी नगर स्टेडियम से शुरू होगी और मेनट कैंपस में समापन होगा।
- उन्होंने बताया कि साइंस मैराथन का आयोजन भोपाल में पहली बार होने जा रहे 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत किया जा रहा है। रन में लगभग 2 हजार से अधिक स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी तथा आमजन शामिल होंगे।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिये चार महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिये चार महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह विकास परियोजनाएँ भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि छोला रेलवे ओवर ब्रिज काली परेड से अयोध्या बायपास भोपाल के निर्माण के लिये मंत्रालय ने 32 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार रेलवे ओवर ब्रिज नेशनल हाई-वे नंबर-7 सिवनी सिटी जिला सिवनी के लिये 126 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किये हैं।
- यह राशि केंद्रीय सड़क और अधो-संरचना कोष अधिनियम 2000 सेतु बंधन योजना में स्वीकृत की गई है।
- इसी प्रकार मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में रेलवे अंडर ब्रिज डबरा रेलवे स्टेशन के पास हरिशंकर पुरम से महलगांव रेलवे ट्रैक ग्वालियर और मोहना रेलवे ओवरब्रिज ग्वालियर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
- मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इससे जिलों के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। बढ़ती सड़क अधो-संरचना से मध्य प्रदेश देश की अर्थ-व्यवस्था में भरपूर योगदान देने में सक्षम बनेगा।

इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली से इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का वर्चुअली लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल शुभारंभ होने से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी। यह उच्चकोटि का अस्पताल है। प्रदेश के लोगों को अब इलाज के लिये दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

- उन्होंने बताया कि उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा इंदौर को चिकित्सा के क्षेत्र में यह बड़ी सौगात दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिये इस हॉस्पिटल में योग, प्राणायाम, व्यायाम जैसी कई तरह की व्यवस्थाएँ हैं। बीमार पड़ने पर अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएँ भी जरूरी होती हैं। इसके लिये यह हॉस्पिटल उपयोगी साबित होगा।

राज्यपाल ने पुरातत्त्व संग्रहालय उज्जैन के नवीन भवन और नई वीथिकाओं का भूमि- पूजन किया

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विक्रम कीर्ति मंदिर उज्जैन स्थित पुरातत्त्व संग्रहालय परिसर में नवीन भवन सहित नई वीथिकाओं का भूमि-पूजन किया। साथ ही राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव ने पुरातत्त्व संग्रहालय का निरीक्षण भी किया।

प्रमुख बिंदु

- उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर संग्रहालय में शहर के समृद्ध इतिहास के कुछ संग्रह हैं, जिसमें लगभग सभी अवधियों, शासकों की कलाकृतियाँ हैं।
- संग्रहालय में प्रागैतिहासिक युग की 650 कलाकृतियाँ और 30 हजार दुर्लभ पांडुलिपियों का विशाल संग्रह है। संग्रहालय का वर्तमान भवन जीर्ण-शीर्ण है। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा संग्रहालय के जीर्णोद्धार तथा उन्नयन का कार्य किया जाएगा। इसके लिये मेसर्स दोशी कंसल्टेंट प्रा. लि. इंदौर को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
- प्रस्तावित कार्य में 1200 वर्गमीटर के नये भवन का निर्माण, 4500 वर्गमीटर के मौजूदा ढाँचे का उन्नयन/नवीनीकरण और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिये नई गैलरी स्थापित करना, वातानुकूलन एवं आधुनिक भंडारण/प्रदर्शन, प्रकाश व्यवस्था और ऑडियो/डिजिटल माध्यम से कलाकृतियों एवं पांडुलिपियों के बारे में जानकारी देना तथा जन-सुविधाएँ विकसित करना आदि शामिल होंगे।
- पुरातत्त्व संग्रहालय भवन निर्माण सहित नई वीथिकाएँ 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। संग्रहालय को आने वाले दिनों में सरकार द्वारा 14 करोड़ रुपए की लागत से सँवारने का कार्य किया जाएगा। इनमें संग्रहालय को अत्याधुनिक रूप देने एवं संरक्षित प्रतिमाओं और अवशेषों को संरक्षित रखने के कार्य किये जाएंगे।
- पुरातत्त्व संग्रहालय में रखी पुरातात्विक धरोहरों, पाँच लाख साल पुराना विश्व प्रसिद्ध हाथी का मस्तक, गेंडे का सींग, दरियाई घोड़े के दाँत, जंगली भैंसे का जबड़ा एवं अन्य 200 जीवाश्म तथा अन्य अवशेषों को विभिन्न वीथिकाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।
- इस संग्रहालय में भीम बेटका के पुरातात्विक उत्खनन में डॉ.विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा एकत्रित आदि मानव द्वारा निर्मित प्रस्तर औजारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- इस संग्रहालय में उज्जैन के राजा चंडप्रद्योत के काल में निर्मित लकड़ी की दीवार एवं बंदरगाह के अवशेष के रूप में गढ़कालिका क्षेत्र स्थित शिप्रा नदी के तट से प्राप्त 10 लट्टे, जो कि 2600 वर्ष पूर्व के हैं, को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में कायथा, महिदपुर, आजाद नगर, रूणिजा, सोडंग, टकरावदा के उत्खनन के साथ प्राप्त चार हजार वर्ष पुरानी पुरातात्विक सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।
- इसके अलावा संग्रहालय में मौजूद दुर्लभ प्रस्तर 472 प्रतिमाएँ, जो कि मौर्यकाल से लेकर मराठकाल तक की हैं, को भी नवनिर्मित वीथिकाओं में प्रदर्शित कर संग्रहालय को समृद्ध बनाने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण तथा 6.5 करोड़ रुपए की लागत से इंटीरियर कार्य कराया जाएगा।

मध्य प्रदेश ट्रांसको ने ऊर्जाकृत किये बैरागढ़ सब स्टेशन में दो नए 220 के.व्ही. के सर्किट

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता एन.पी. गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश ट्रांसको कंपनी ने 220 के.व्ही. के दो नए सर्किट (फीडर और लाइन) को ऊर्जाकृत करने में सफलता हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश ट्रांसको कंपनी द्वारा 220 के.व्ही. सब स्टेशन बैरागढ़ भोपाल में 10 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से निर्मित 220 के.व्ही. के दो नए सर्किट (फीडर और लाइन) को ऊर्जाकृत किया गया, जिससे बैरागढ़ जहाँ 400 के.व्ही. सब स्टेशन आष्टा से सीधा जुड़ गया है, वहीं 400 के.व्ही. सब स्टेशन भोपाल से भी एक अतिरिक्त 220 के.व्ही. सर्किट बैरागढ़ में उपलब्ध हो गया है।
- कंपनी के अधीक्षण अभियंता एन.पी. गुप्ता ने बताया कि कंपनी यह व्यवस्था करने में इसलिये सफल हुई, क्योंकि कुछ समय पूर्व 400 के.व्ही. सब स्टेशन आष्टा में 315 एम.व्ही.ए. क्षमता का एक पावर ट्रांसफॉर्मर ऊर्जाकृत किया गया था, जिससे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को सेंटर ग्रिड से अतिरिक्त बिजली मिल पाई है और इसका फायदा भोपाल को मिल पाया।
- उन्होंने बताया कि 220 के.व्ही. सब स्टेशन बैरागढ़ में पहले 220 के.व्ही. की सप्लाई 400 के.व्ही. सब स्टेशन सूखीसेवनिया भोपाल से 220 के.व्ही. के दो सर्किटों के माध्यम से प्राप्त होती थी।
- एन.पी. गुप्ता ने बताया कि नए 220 के.व्ही. सर्किट के निर्माण से बैरागढ़ से जुड़े 132 के.व्ही. आईटी पार्क, ईटखेड़ी, रूहाना, श्यामपुर कुरावर, सीहोर, लालघाटी सबस्टेशन को फायदा पहुँचेगा, जहाँ 132 के.व्ही. वोल्टेज स्तर की गुणवत्तापूर्ण विद्युत का पारेषण हो सकेगा।

सिंगरौली को मिलेगा मेडिकल कॉलेज भवन की सौगात

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के मुताबिक 22 जनवरी को सिंगरौली में शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन का शिलान्यास किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि सिंगरौली जिला ताप विद्युत केंद्रों और कोयला खनन परियोजनाओं के कारण प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण ग्राम नौगढ़ में किया जा रहा है। इसके लिये 25 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। भवन परिसर निर्माण के लिये 248 करोड़ 27 लाख रूपए मंजूर किये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि इसका निर्माण मेसर्स डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो 19 दिसंबर, 2024 तक पूरा होगा।
- शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मेडिकल कॉलेज बन जाने से यहाँ उपचार की व्यवस्थाएँ बेहतर होंगी। सिंगरौली ही नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र के विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा होगा। जनजातीय बहुल अंचल के विद्यार्थी अपने घर के समीप रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे।
- मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये वरिष्ठ डॉक्टरों तथा अनुभवी प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। उनके मेडिकल ज्ञान और दक्षता का लाभ सिंगरौली जिले को मिलेगा।

गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

20 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति एवं टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव और प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पांच दिवसीय गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल प्रदेश के मंदसौर जिले में 1 फरवरी से आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन और संस्कृति एवं टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव और प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मंदसौर में आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा ग्लैपिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का अनुभव देने वाला यह अद्वितीय और अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, जिसमें लैंड, एयर और वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज रहेगी।

- यह महोत्सव 5 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 3 माह तक पर्यटकों के लिये टेंट सिटी (ग्लैंपिंग) और 6 माह तक एडवेंचर एक्टिविटीज जारी रहेगी तथा पर्यटकों के रिस्पॉन्स पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।
- शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिये एक शानदार त्योहार है, जो उन्हें शहर की हलचल से दूर प्राकृतिक परिवेश में ले जाता है।
- फ्लोटिंग फेस्टिवल में फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग मार्केट, बोट स्पा, बोट सफारी, लाइव संगीत तथा अन्य का भी आयोजन होगा। इसके अलावा, गांधीसागर जलाशय के पास कई रोमांचक साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
- गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में प्रत्येक लक्जरी टेंट को प्रीमियम सुविधाओं, मनोरम, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों, इंडोर स्पोर्ट्स सम्मेलन सुविधाओं के साथ आरामदायक प्रवास सुनिश्चित करने के लिये सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है।
- प्रकृति आधारित शिल्प के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिये, क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी। यह पर्यावरण के अनुकूल शिल्प कौशल के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है।
- उल्लेखनीय है कि गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार की नई संभावनाएँ पैदा करने के लिये शुरुआती 10 साल की पहल है।
- शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिससे उन्हें मध्य प्रदेश के विभिन्न आकर्षण का अनुभव करने का मौका मिलेगा। राज्य के भीतर कई गंतव्यों की खोज की जा रही है, जिनमें सफल पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित होने की क्षमता है।

मुख्यमंत्री द्वारा पुस्तक 'वेलोपेथी-माय नेचुरल हीलर'का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

20 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित सभागार में स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोगी पुस्तक 'वेलोपेथी-माय नेचुरल हीलर'का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 'वेलोपेथी-माय नेचुरल हीलर'पुस्तक के लेखक रतलाम जिले के नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉ. संतोष गुप्ता हैं।
- पुस्तक 'वेलोपेथी'का मुख्य उद्देश्य आधुनिक जीवन-शैली के साथ समाज को स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर अग्रसर करना है। इस पुस्तक का प्रयास यह होगा कि मॉडर्न मेडिसिन का प्रयोग किये बिना व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन सके।
- सात अध्यायों में विभाजित इस पुस्तक में जीवन-शैली के तीन आयाम फूड, उठने-बैठने के तरीके और माइंड पर जानकारी दी गई है। इसमें वेलोपेथी के सिद्धांत, शरीर के नियम, बीमारियाँ और उनसे सुरक्षा, आहार एवं पोषण के सिद्धांत, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, एलर्जिक फूड और जीवन-शैली पर चित्रों तथा सरल भाषा में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है।

चित्रकूट में गुप्त गोदावरी में नजर आई तीसरी गुफा

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के सतना के मझगावां के एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने बताया कि भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट के मध्य प्रदेश क्षेत्र में गुप्त गोदावरी के समीप तीसरी गुफा नजर आई है। जल्द ही पुरातत्व विभाग की टीम को बुलाकर जानकारी कराई जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने बताया कि गुफा की लंबाई लगभग 25 फीट व चौड़ाई डेढ़ मीटर है। अँधेरा होने के चलते मझगावां के एसडीएम व कई अधिकारियों की टीम महज 12 फीट अंदर ही जा सकी। अँधेरे की वजह से अधिकारी आधी दूरी तक ही पहुँचे हैं।
- विदित है कि पौराणिक काल से चित्रकूट धर्मनगरी खुद के ऐतिहासिक महत्त्व को संजोए हुए है। धर्मनगरी की प्राकृतिक पहाड़ियों की कंदराओं व गुफाओं में साधु-संत तपस्या में लीन हैं, जिनके दर्शन बेहद दुर्लभ होते हैं। धर्मनगरी के तमाम ऐसे रहस्य हैं, जो अब तक पहुँच से दूर हैं।

सौर ऊर्जा से रोशन होगी साँची

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित साँची की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बिजली आपूर्ति में आत्म-निर्भर बनाने के लिये इसे प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि साँची रायसेन ज़िले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, जो कि स्तूप और बौद्ध तीर्थ स्थल के लिये विख्यात है।
- साँची में शिविर के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने परिसर में सोलर रूफटॉप लगवाने का आह्वान किया गया है और सोलर रूफटॉप के लाभ के बारे में बताते हुए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि साँची में सौर ऊर्जा के माध्यम से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे साँची बिजली आपूर्ति में आत्म-निर्भर होने के साथ ही अगले पाँच वर्षों की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा से सुनिश्चित होगी।
- साँची में सौर स्ट्रीट लाइट, गार्डन लाइट, स्टड लाइट, हाई - मास्ट लाइट, सौर पेयजल कियोस्क, लोक परिवहन के लिये बैट्री चलित ई-रिक्शा, चार्जिंग स्टेशन, अक्षय ऊर्जा, आधारित संयंत्र विंड टर्बाइन एवं पिजोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स स्थापना के कार्य भी किये जाएंगे।

13वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों पर 25 जनवरी को 13वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंवेशन सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम 13वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया जाएगा।
- 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम प्रदेश के सभी 52 ज़िलों में किये जाएंगे। साथ ही प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों और शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाई जाएगी।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल पटेल द्वारा निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िला निर्वाचन अधिकारी, उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्ष 1951-52 में हुए प्रथम आम चुनाव से लेकर वर्ष 2018-2019 में हुए निर्वाचनों में मतदाताओं एवं निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधि के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता जागरूकता को लेकर प्रतियोगिता कराई गई थी। निबंध, स्लोगन, गीत, पोस्टर सहित अन्य प्रतियोगिताएँ हुई थीं। देशभर में मध्य प्रदेश के 7 प्रतिभागी विजेता बने।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भोपाल में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र के साथ अवार्ड के रूप नकद राशि प्रदान की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि 13वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस बार 'वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम' थीम पर मनाया जाएगा।
- विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 'मैं भारत हूँ' गीत का शुभारंभ किया जाएगा। मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाएँ, मतदान केंद्र पर मिलने वाली न्यूनतम सुविधाओं सहित मतदाताओं को डाक मतपत्र, ईवीएम वीवीपैट, वोटर हेल्पलाइन एप और नैतिक मतदान के बारे में कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी।

नाबार्ड 2023-24 में मध्य प्रदेश को 2 लाख 58 हजार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक-नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने 'राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24' में बताया कि नाबार्ड मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिये वर्ष 2023-24 के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2 लाख 58 हजार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.43 प्रतिशत ज्यादा है।

प्रमुख बिंदु

- 2 लाख 58 हजार 598 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता में कृषि के लिये 1 लाख 80 हजार 160 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिये 65 हजार 832 करोड़ रुपए और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये 12 हजार 606 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी में कहा कि नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण सहयोग से किसानों, उद्यमों से जुड़े कामगारों और राज्य की पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की 5 ट्रिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के 550 बिलियन डॉलर के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- संगोष्ठी में वित्त मंत्री ने राज्य फोकस पेपर 2023-24 तथा 550 बिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लिये 'मध्य प्रदेश में कृषि ऋण प्रमुख मुद्दे' पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राज्य के सराहनीय प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण आकलन में कृषि, एमएसएमई एवं सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 70 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत आँकी गई है।
- नाबार्ड के सहयोग से जल-संसाधन, कृषि मशीनीकरण, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, मछली पालन, भंडार-गृह निर्माण, खाद्य प्र-संस्करण, नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन होगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति किये जाने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में संचालित म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन में सभी जिलों में उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिन्हें राज्य शासन एवं केंद्र शासन से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधो-संरचना और अन्य विकास कार्यों के लिये 'मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधो-संरचना निर्माण योजना' के अंतर्गत दो वर्षों के लिये (वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24) 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिये जाने एवं आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 85 पी.जी. सीट वृद्धि के लिये 101 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के विभिन्न विभागों में पी.जी. सीट की वृद्धि से प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
- मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसर तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों के निजी सहभागिता से संचालन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 'संविदा शाला शिक्षक' को 'प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक' से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

ओरछा में 550 किमी. की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

23 जनवरी, 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 6800 करोड़ रुपए की लागत वाली 550 किमी. की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बेतवा में 665 मीटर लंबे पुल का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 2-लेन पेव्ड शोल्डर ब्रिज तथा फुटपाथ के निर्माण के साथ ओरछा, झाँसी, टीकमगढ़ की कनेक्टिविटी में सुधार आ जाएगा।
- पवई, ओरछा, हरपालपुर, कैथी पढरिया कला, पटना तमौली, जस्सो, नागौड़ तथा सागर लिंक रोड बाईपास के निर्माण से नगर में यातायात का दबाव कम होगा। सागर ग्रीनफील्ड लिंक मार्ग से भोपाल से कानपुर की दूरी मोहरी से समाई घाट और चौक होते हुए मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश तक 21 किमी. कम हो जाएगी।
- गडकरी ने कहा कि सीमा तक 4 लेन चौड़ा करने से यात्रा के समय में भारी कमी आ जाएगी। सागर शहर, छतरपुर शहर तथा गढ़ाकोटा में फ्लाईओवर के निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों- ओरछा, खजुराहो, पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़, साँची तक पहुँचने के लिये कनेक्टिविटी सरल हो जाएगी।
- उन्होंने कहा कि भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे के निर्माण से सीमेंट और खनिज अवयवों का परिवहन सरल हो जाएगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाएगी। इस गलियारे के निर्माण के साथ भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी का संपर्क अच्छा हो जाएगा। टीकमगढ़ से ओरछा तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क के निर्माण से यातायात सुरक्षित हो जाएगा।
- इस कार्यक्रम में गडकरी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से बमीठा से सतना तक 105 किमी. लंबाई वाली 4 लेन की ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इस मार्ग के निर्माण के साथ, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

राज्यपाल ने गणतंत्र का उत्सव 'लोकरंग' का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र का उत्सव 'लोकरंग' का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्सव में साहित्यकारों को राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया तथा गणतंत्र दिवस समारोह के विजेताओं को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि रवींद्र भवन परिसर, भोपाल में 30 जनवरी तक लोकरंग उत्सव मनाया जाएगा।
- लोकरंग के केंद्र में 'विमुक्त एवं घुमंतू' विषय को रखा गया है। लोकरंग में यूक्रेन, यूके, इजिप्ट के साथ देश के 12 राज्य के लोक नृत्य की प्रस्तुतियाँ होंगी। लोकरंग में राजस्थान समुदाय के कालबेलिया समुदाय के जीवन पर एकाग्र 'चरैवेति' समवेत नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई। इसमें कालबेलिया समुदाय की जीवन परंपरा, संस्कृति को दिखाया गया।
- लोकरंग उत्सव में विविध शिल्प माध्यमों के शिल्पों का मेला 'हुनर', कलात्मक दीपकों की प्रदर्शनी 'अभ्यर्थना', कला एवं संस्कृति विषयक पुस्तकों का 'पुस्तक मेला', देशज व्यंजन 'स्वाद' प्रदर्शनी, गायन प्रस्तुति पर 'लोकराग' आदि मुख्य आकर्षण हैं।
- इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल और प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने साहित्यकारों को राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया।
 - ◆ राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2021से हिन्दी के क्षेत्र में सुदीर्घ उत्कृष्ट सृजनात्मक अवदान के लिये डॉ. श्याम सुंदर दुबे को विभूषित किया।
 - ◆ राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2021से हिन्दी साहित्य के शोधपरक लेखन और उत्कृष्ट सृजनात्मक सुदीर्घ अवदान के लिये डॉ. सदानंद प्रसाद गुप्त को विभूषित किया।
 - ◆ राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान वर्ष 2021से ललित निबंध के क्षेत्र में प्रासंगिक अध्ययनपरक अभिव्यक्ति के लिये डॉ. श्रीराम परिहार को विभूषित किया।

- ◆ राष्ट्रीय इकबाल सम्मान वर्ष 2021 डॉ. सैयद तकी हसन आबिदी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि को प्रदान किया गया।
- ◆ राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2021 से जनजाति कल्याण केंद्र महाकोशल, बरगाँव डिंडोरी को समाज सेवा के क्षेत्र में बुनियादी एवं सार्थक सरोकारों को केंद्र में रखकर किये जा रहे व्यावहारिक कार्यों के लिये विभूषित किया।
- राज्यपाल और मंत्री उषा ठाकुर ने संस्कृति विभाग के एम.पी. कल्चर एप का शुभारंभ किया। एम.पी. कल्चर एप में संस्कृति विभाग के आयोजनों की जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम की लाइव लिंक भी एप में उपलब्ध रहेगी। साथ ही प्रदेश की विभिन्न कला विधाओं की जानकारी भी एप से प्राप्त हो सकेगी।
- राज्यपाल पटेल और मंत्री उषा ठाकुर ने गणतंत्र दिवस परेड, लोक-नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और झाँकियों के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
- ◆ झाँकियों में पहला स्थान जेल विभाग, दूसरा स्थान पर्यटन विभाग और तीसरा स्थान वन विभाग ने प्राप्त किया।
- ◆ सैन्य दलों की श्रेणी में पहला स्थान हॉक फोर्स, दूसरा विशेष सशस्त्र बल और तीसरा स्थान एसटीएफ प्लाटून को प्रदान किया गया।
- ◆ असैन्य दल की श्रेणी में पहला स्थान भूतपूर्व सैनिक, दूसरा एनसीसी एयर विंग, तीसरा स्थान संयुक्त रूप से सीनियर डिविजन एनसीसी आर्मी विंग (गर्ल्स) और एनसीसी नेवल विंग को प्रदान किया गया।
- ◆ विद्यालयों में पहला स्थान शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दूसरा हेमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेल और तीसरा स्थान मानसरोवर पब्लिक स्कूल ने प्राप्त किया।
- ◆ लोक नृत्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में पहला स्थान भील भगोरिया जनजातीय लोक नृत्य, दूसरा स्थान कोरकू थाटिया लोक नृत्य और तीसरा स्थान गुदुम बाजा लोक नृत्य को मिला।

प्रदेश की चार विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों 'पद्म पुरस्कारों'की घोषणा की गई। इनमें मध्य प्रदेश के चार विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023 के लिये राष्ट्रपति ने तीन द्वय मामलों (एक द्वय मामले में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है।
- सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएँ हैं और विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।
- पद्म पुरस्कार के लिये चयनित मध्य प्रदेश के चार विभूतियों में श्रीमती जोधइया बाई, डॉ. मुनीश्वर चंदावर और श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार (संयुक्त रूप से) शामिल हैं।
- जनजातीय कला को संरक्षित कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करने के लिये उमरिया की बैगा जनजातीय कलाकार जोधइया बाई को कला के क्षेत्र में, चिकित्सा को सेवा का अटल संकल्प बनाकर मानव कल्याण को नई दिशा देने वाले जबलपुर के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. मुनीश्वर चंदावर को मेडिसिन के क्षेत्र में, झाबुआ के कलाकार रमेश परमार एवं शांति परमार को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित किया गया है।
- गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
- यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं।
- असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म भूषण' और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म श्री'से सम्मानित किया जाता है।
- ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाते हैं।

मध्य प्रदेशीय और भारतीय देशी गायों के लिये नवीन पुरस्कार योजना

चर्चा में क्यों ?

27 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 'प्रदेश की मूल गो-वंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिये पुरस्कार योजना' लागू की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- पशुपालन मंत्री ने बताया कि देश-प्रदेश की देशी नस्लों के गोपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना में 1 से 15 फरवरी तक प्रदेश की मूल और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों की प्रतियोगिताएँ होंगी।
- इस प्रतियोगिता में 201 जिलास्तरीय पुरस्कार दिये जाएंगे, जो 45 मध्य प्रदेश के मूल गोवंशीय और 156 भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के लिये होंगे। इसके अलावा 6 राज्यस्तरीय पुरस्कार भी दिये जाएंगे।
- प्रदेश की मूल गोवंशीय और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की प्रतियोगिता जिलों में अलग-अलग की जाएगी। प्रदेश की मूल गोवंशीय नस्ल प्रतियोगिता 15 जिलों- आगर-मालवा, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी में की जाएगी।
- मालवी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता जिला आगर-मालवा, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन और इंदौर में तथा निमाड़ी नस्ल की जिला खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार और केनकथा नस्ल की प्रतियोगिता जिला दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिले में होगी।
- पशुपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश की मूल गोवंशी नस्ल- मालवी, निवाड़ी और केनकथा गाय का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन 4 लीटर या अधिक और भारतीय गाय का 6 लीटर या उससे अधिक होना चाहिये।
- भारतीय उन्नत नस्ल गाय प्रतियोगिता सभी 52 जिलों में होगी। अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को पुरस्कार दिया जाएगा।
- दोनों प्रतियोगिताओं में जिलास्तरीय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 51 हजार, 21 हजार और 11 हजार रुपए होंगे। इसी तरह राज्यस्तरीय पुरस्कार भी क्रमशः 2 लाख, 1 लाख और 50 हजार रुपए का होगा।
- तीनों पुरस्कार के अलावा शेष प्रतियोगी गायों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त समस्त पशुपालकों की सूची मय गायों की नस्ल और दुग्ध उत्पादन ब्योरे के साथ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

'यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज' प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की दो युवतियाँ चयनित

चर्चा में क्यों ?

28 जनवरी, 2023 को गैर-सरकारी संगठन 'यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज' प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आभा शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय 'यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज' प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भारत की चार युवतियों का चयन हुआ है, जिनमें से दो युवतियाँ मध्य प्रदेश की हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आभा शर्मा ने बताया कि 'यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज' प्रोजेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की चार युवतियों का चयन हुआ है, जिनमें से दो युवतियाँ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के महेंद्रा ग्राम की सोनाली विश्वकर्मा और गुना की वर्षा जाटव हैं।
- आभा शर्मा ने बताया कि 'यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज' प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के महेंद्रा ग्राम की सोनाली विश्वकर्मा और गुना की वर्षा जाटव का चयन हुआ है। अन्य दो युवतियाँ खुशबू और काजल कनौजिया उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की हैं। ये चारों युवतियाँ इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
- इस प्रोजेक्ट का कोलॉबोरेशन भारत में कार्यरत संस्था 'मिलान फाउंडेशन' और नेपाल में कार्यरत संस्था 'पीआरसी' के साथ है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये युवतियाँ यूथ की आवाज को विश्व स्तर पर पहुँचाएंगी।

लाडली बहना योजना

चर्चा में क्यों ?

28 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ज़िले में नर्मदा जयंती एवं नर्मदापुरम के गौरव दिवस पर 'लाडली लक्ष्मी योजना' की तरह प्रदेश में 'लाडली बहना योजना' शुरू किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में सभी वर्गों की गरीब बहन को प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलेंगे और यदि उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वह पूर्ववत् मिलता रहेगा।
- इस योजना पर 5 वर्षों में अनुमानित 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों की जिंदगी को और बेहतर बनाएगी तथा प्रदेश की महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।
- इस गौरव दिवस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम ज़िले को अनेक विकास कार्यों की सौगात देते हुए श्री महाकाल लोक की तर्ज पर नर्मदापुरम लोक और नर्मदा कॉरीडोर बनाने की घोषणा की। साथ ही यहाँ आधुनिक बस स्टैंड भी बनाया जाएगा।
- नर्मदा जयंती और गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का जल मंच से वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें प्रमुख रूप से 11 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन आयुक्त नर्मदापुरम के भवन का लोकार्पण, 1 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से रामलीला मैदान के उन्नयन, 2 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री अधो-संरचना एवं विभिन्न विकास कार्य और 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत वाले नगर के ऑडिटोरियम का वर्चुअली भूमि पूजन किया।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मेघा इंजीनियरिंग के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश में 17 अति उच्चदाब सबस्टेशन बनाने के लिये मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच टी.एस.ए. (ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर हुए।

प्रमुख बिंदु

- इसके पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त बिड प्रोसेस को-ऑर्डिनेटर आर.ई.सी.पी.डी.सी.एल. ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यूनतम बिडर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद को एस.पी.ए. (शेयर परचेस एग्रीमेंट) हस्तांतरित किया।
- मुख्य अभियंता संजय कुलश्रेष्ठ ने बताया कि टी.बी.सी.बी. (टेरिफ बेस्ड कांपेटिटिव बिडिंग) में न्यूनतम रहते हुए मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिये 17 अति उच्चदाब के सबस्टेशन बनाने का यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है।
- 17 अति उच्चदाब के सबस्टेशन में 400 के.वी. का एक, 220 के.वी. के 3 तथा 132 के.वी. के 13 सबस्टेशन शामिल हैं। इनमें मध्य क्षेत्र के 10 तथा पश्चिम क्षेत्र के 7 सबस्टेशन शामिल हैं।
- मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 59 दौरे की ई-रिवर्स ऑक्सन प्रक्रिया के बाद यह टेंडर मिला है। आदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा टेकनो इलेक्ट्रिक एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अंतिम दौरे की टेंडर प्रक्रिया में शामिल थीं।
- इस पैकेज में भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में प्रदेश का पहला 400 के.वी. जी.आई.एस. सबस्टेशन, भोपाल में ही 132/33 के.वी. का दूसरा जी.आई.एस. सबस्टेशन एच.ओ.डी., भोपाल क्षेत्र में होशंगाबाद ज़िले के बिसोनीकला, बैतूल ज़िले के शाहपुर में 220 के.वी. का, राजगढ़ ज़िले के छापीहेडा, हरदा ज़िले के सोदालपुर, रायसेन ज़िले के पठारी, और बाड़ी, सीहोर ज़िले के जावरजोड, अशोकनगर ज़िले के सेमराहत में 132 के.वी. के सबस्टेशन, धार ज़िले के पीथमपुर में 132/33 के.वी. का जी.आई.एस. सबस्टेशन, खरगोन में 220 के.वी. का सबस्टेशन, उज्जैन ज़िले के भाटपचलाना, खरगोन ज़िले के पीपलगाँव, रतलाम ज़िले के धोदर, देवास ज़िले के चोबराधीर, अलीराजपुर ज़िले के अंबजा में 132/33 के.वी. के सबस्टेशन बनाए जाएंगे।
- निर्माण करने के बाद इन सबस्टेशनों का संचालन 35 वर्षों के लिये मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।